मुख्य समाचार :–

- **सरकार ने राज्य के सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति दी।**
- **प्रदेश में पीएम–श्री विद्यालयों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर तीन सदस्यीय समिति बनाई जाएगी।**
- **गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने कहा– चारधाम यात्रा संचालन का निर्णय मौसम ठीक होने के बाद लिया जाएगा।**
- **प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज भारी बारिश का ऑरेंज और यलो अलर्ट।**

महंगाई भत्ता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति दी है। पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 455 प्रतिशत से बढ़ाकर 466 प्रतिशत और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का भत्ता 246 प्रतिशत से बढ़ाकर 252 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी।

वित्तीय स्वीकृति

शासन ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसमें पिथौरागढ़ जिला कारागार में अतिरिक्त आवासीय भवनों के निर्माण के लिए चार करोड़ रुपए से अधिक, जबकि रुड़की उपकारागार में नवीन आवासीय भवनों के लिए ढाई करोड़ रुपए की मंजूरी शामिल है। वहीं, धारचूला विधानसभा क्षेत्र के रालम के अंतर्गत किलातम में चैकडाम निर्माण के लिए 95 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसमें प्रथम किश्त के रूप में 57 लाख रुपये जारी किए गए हैं। चम्पावत विधानसभा क्षेत्र में हनुमान मंदिर मेला स्थल लधौली, ऐड़ी मेला स्थल कालूखाण और फुटलिंग कालूखाण के सौंदर्यीकरण कार्य के लिए इक्यासी लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए पहली किश्त के रूप में लगभग 49 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

समिति निर्माण

प्रदेश में पीएम–श्री विद्यालयों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर तीन सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता वाली यह समिति निर्माण और खरीद–फरोख्त की निगरानी करेगी। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के निर्माण और मरम्मत के लिए राज्य सरकार ने आपदा मोचन निधि से 20 करोड़ रुपये जारी किए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिला शिक्षा समिति की अध्यक्षता में प्रस्ताव शीघ्र भेजकर निर्माण कार्य पूरे कराए जाएं। डॉक्टर रावत ने कहा कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि 15 सितम्बर तक डीबीटी के माध्यम से छात्रों के खातों में स्कूल बैग, जूते, ड्रेस और साइकिल की खरीद के लिए अनिवार्य रूप से भेजी जाए। उन्होंने अधिकारियों को आवासीय स्कूलों, कस्तूरबा गांधी

आवासीय विद्यालयों, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय और अन्य संस्थानों का नियमित निरीक्षण कर भोजन, साफ–सफाई और आवासीय व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।

चारधाम यात्रा संचालन पर निर्णय

गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने कहा है कि चारधाम यात्रा संचालन का निर्णय मौसम ठीक होने के बाद लिया जाएगा। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए चारधाम यात्रा पर 5 सितंबर तक रोक लगाई गई है। आयुक्त ने बताया कि गढ़वाल मंडल के सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं और आपदा के समय फोन नहीं उठाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिरीक्षण, गढ़वाल राजीव स्वरूप ने कहा कि आपदा को देखते हुए पुलिस की 65 टीमें विभिन्न क्षेत्रों में तैनात हैं। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ लगातार अलर्ट मोड पर हैं।

मौसम

उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में हो रही लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन व्यापक रूप से तरह प्रभावित हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जलभराव होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मौसम विभाग ने आज देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधमसिंह और बागेश्वर में कहीं–कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के अन्य जिलों में भी गरज के साथ वर्षा का यलो अलर्ट है।

भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल और चम्पावत जिले में आज स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है।

स्थलीय निरीक्षण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश से प्रभावित हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र का ट्रैक्टर से दौरा कर आपदा प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानीं और जिला प्रशासन को राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत शिविरों में भोजन, पानी, दवाइयों और साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने, जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने, किसानों की फसल क्षति का त्वरित आकलन कर मुआवजा प्रक्रिया शुरू करने और आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन–प्रशासन स्तर पर सभी आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं ताकि प्रभावित लोगों को राहत मिल सके।